भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *248

जिसका उत्तर 17 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल

***248. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुणे जिले में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल स्थापित करने के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल (ईएमसी 2.0) योजना अथवा किसी अन्य पहल के अंतर्गत कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों, पहचान की गई कुल भूमि, अनुमानित निवेश और अनुमोदन तथा विकास के लिए अपेक्षित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित संकुलों में इकाइयों के लिए भूमि, अवसंरचना, सामान्य सुविधा केन्द्र और 'प्लग-एंड-प्ले' सहायता प्रदान करने में महाराष्ट्र राज्य सरकार की क्या भूमिका है;

(घ) क्या महाराष्ट्र से किन्हीं आवेदनों को इएमसी 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया है अथवा उन पर विचार किया जा रहा है**;**

(ड.) पुणे संकुल का प्रत्याशित रोजगार सृजन, आकर्षित की जाने वाली संभावित इकाइयों की संख्या और घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात में संभावित योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स संकुलों की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(च):** एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल" के संबंध में दिनांक 17.12.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *248 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

.....

(क) से **(च):** भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिकी नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विज़न से प्रेरित है। इसके तहत पूरे इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितकी तंत्र के निर्माण और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु उद्योग जगत के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

नीतिगत रणनीति में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के लिए आवश्यक तैयार उत्पाद, मॉड्यूल, संघटक, सब-मॉड्यूल, उपकरण, कच्चा माल और मशीनरी का विनिर्माण शामिल है।

इस व्यापक और पारिस्थितकी तंत्र पर आधारित पहल के परिणामस्वरूप, भारत ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन (₹)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि हुई
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात (₹)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि हुई
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि हुई
मोबाइल फ़ोन का निर्यात (₹)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि हुई

इस विज़न के अनुसार, सरकार ने अप्रैल 2020 में संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना अधिसूचित की।

इस योजना के तहत सामान्य सुविधाओं वाले समर्पित क्लस्टर के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर विश्वस्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण अवसंरचना के सृजन में सहायता दी जाती है।

ये क्लस्टर साझा अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें तैयार औद्योगिक प्लॉट, रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड और प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं शामिल हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण यूनिटें तेज़ी से स्थापित की जा सकें।

इस योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर को मंज़ूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 492.85 करोड़ है। यह 297.11 एकड़ एरिया में फैला हुआ है।

इस प्रस्ताव से ₹2,000 करोड़ के निवेश और रोजगार के 5000 अवसर पैदा होने का अनुमान है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) इस परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के तौर पर काम कर रहा है।

इस परियोजना के लिए भारत सरकार से ₹207.98 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और शेष राशि एमआईडीसी द्वारा प्रदान की जाएगी।

<u>राज्य सरकार की भूमिका</u>

- राज्य सरकार पीआईए के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए ज़िम्मेदार है।
- यह कानूनी मंज़ूरी, अवसंरचना आयोजना और विकास का काम करता है।
- इसमें सामान्य सुविधाओं का सृजन और क्लस्टर में यूनिटों के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।
- यह क्लस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण यूनिटें स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने ईएमसी योजना के तहत महाराष्ट्र में दो सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए अनुमोदन प्रदान किया है:

जगह	**कुल परियोजना लागत (₹ करोड़)**	**भारत सरकार की वित्तीय सहायता (₹ करोड़)**
पिंपरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे	67.00	50.00
शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर	41.09	29.29

ये सीएफसी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन, आदिरूप निर्माण, परीक्षण और मापन के लिए साझा सुविधाएं प्रदान करते हैं।

*****